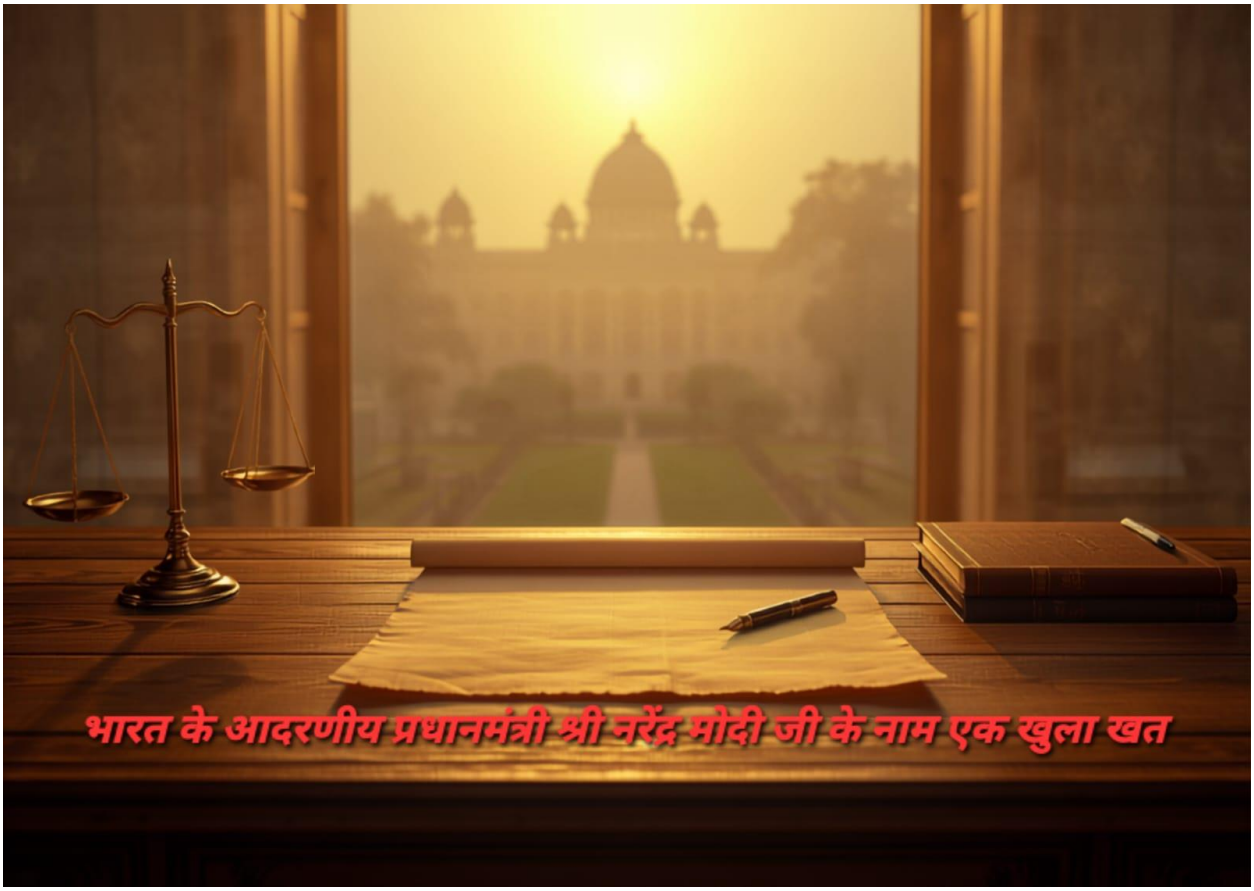

भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम एक खुला खत

विषय: 'विकसित भारत' के निर्माण में भारतीय मुसलमानों की भागीदारी, नई योजनाओं की रूपरेखा और एक नए जमीनी मूल्यांकन (कमेटी) का आग्रह।

माननीय प्रधानमंत्री जी,

आपके कुशल नेतृत्व में भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। आपका नारा **'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास'** महज़ एक नारा नहीं, बल्कि एक नए और मज़बूत भारत की बुनियाद है। पिछले एक दशक में आपकी सरकार ने 'उज्ज्वला योजना', 'पीएम आवास योजना', 'आयुष्मान भारत', 'जन धन योजना'

और 'मुद्रा लोन' जैसी जो 'अम्ब्रेला स्कीम्स' (Umbrella Schemes) चलाई हैं, उनका लाभ देश के हर वर्ग को मिला है। इन योजनाओं ने बिना किसी धार्मिक या जातीय भेदभाव के करोड़ों गरीब मुसलमानों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाने का काम किया है, जिसके लिए देश का मुस्लिम समाज आपके प्रयासों की दिल से सराहना करता है।

प्रधानमंत्री जी, आपका सपना 2047 तक भारत को एक 'विकसित राष्ट्र' (Developed Nation) और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का है। लेकिन यह एक हक़ीक़त है कि देश की लगभग 15 प्रतिशत आबादी (मुस्लिम समाज) को आर्थिक और शैक्षिक रूप से पीछे छोड़कर इस महान लक्ष्य को पूरी गति से हासिल नहीं किया जा सकता।

सच्चर और कुंडू कमेटी की याद और नए डेटा की ज़रूरत: आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2006 में आई 'सच्चर कमेटी' और 2014 में आई प्रोफ़ेसर अमिताभ कुंडू की 'पोस्ट-सच्चर इवैल्यूएशन कमेटी' ने देश के सामने एक कड़वा सच रखा था। उन रिपोर्ट्स ने स्पष्ट रूप से बताया था कि भारतीय मुसलमान शिक्षा, सरकारी रोज़गार और बैंकिंग सुविधाओं के मामले में देश के सबसे पिछड़े वर्गों (कई पैमानों पर दलितों से भी पीछे) में गिने जाते हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में स्कूलों और अस्पतालों की कमी, और कारीगरों को बैंक लोन न मिलने जैसी गंभीर समस्याएं उन रिपोर्ट्स में उजागर हुई थीं।

आज कुंडू कमेटी की रिपोर्ट को आए हुए एक दशक से ज़्यादा (12 साल) का वक्त गुज़र चुका है। आपकी सरकार ने इस दौरान कई बड़े काम किए हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी और बदलते आर्थिक हालात के बाद, आज ज़मीन पर मुसलमानों की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या वे मुख्यधारा से जुड़ पाए हैं या उनका पिछड़ापन और बढ़ा है? यह जानने के लिए हमारे पास आज कोई ठोस, नया और प्रामाणिक (Authentic) सरकारी डेटा नहीं है।

हमारी आपसे मुख्य मांगें और सुझाव:

एक मज़बूत और समावेशी (Inclusive) भारत के निर्माण के लिए, हम आपसे निम्नलिखित दो प्रमुख कदम उठाने की गुज़ारिश करते हैं:

1. सच्चर और कुंडू कमेटी की तर्ज़ पर एक 'नई उच्च स्तरीय जांच कमेटी' का गठन: हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि वर्तमान हालात का जायज़ा लेने के लिए एक नई राष्ट्रीय स्तर की कमेटी बनाई जाए। यह कमेटी इस बात का डेटा इकट्ठा करे कि:

- आपकी शानदार 'अम्ब्रेला स्कीम्स' का फायदा ज़मीन पर मुस्लिम समाज को कितना पहुंचा है?
- शिक्षा और रोज़गार (खासकर फॉर्मल सेक्टर) में मुसलमानों का आज का प्रतिशत क्या है?
- क्या बैंकों ने मुस्लिम बहुल इलाकों को "रेड ज़ोन" मानना बंद कर दिया है? *एक नई रिपोर्ट सरकार को यह समझने में मदद करेगी कि नीतियों को और ज़्यादा असरदार कैसे बनाया जाए। बिना ताज़ा डेटा के, सही इलाज और नीतियां बनाना संभव नहीं है।*

2. मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कुछ नई और लक्षित (Targeted) योजनाएं: हम चाहते हैं कि आपकी सरकार, कुंडू कमेटी के सुझावों को ध्यान में रखते हुए, कुछ नई योजनाएं डिज़ाइन करे:

- **'विद्यार्थी उड़ान योजना' (शिक्षा के लिए):** मुसलमानों में ड्रॉप-आउट रेट (बीच में पढ़ाई छोड़ना) सबसे ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि एक ऐसी विशेष स्कॉलरशिप या योजना आए जो मुस्लिम बहुल इलाकों में मिडिल और हाई स्कूल के छात्रों (खासकर लड़कियों) को उच्च शिक्षा (Higher Education) तक ले जाए। मदरसों के आधुनिकीकरण के साथ-साथ 'स्टेम' (STEM: Science, Technology, Engineering, Math) शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष फंड बनाया जाए।
- **'हुनरमंद भारत - कारीगर विकास योजना' (रोज़गार के लिए):** मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बुनकरी, हस्तशिल्प (हैंडीक्राफ्ट), कार-रिपेयरिंग और छोटे व्यवसायों में लगा है। बिचौलियों (Middlemen) के कारण ये गरीब ही रह जाते हैं। 'पीएम विश्वकर्मा योजना' की तर्ज़ पर एक ऐसी विशेष योजना बने जो इन मुस्लिम कारीगरों को सीधे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स बाज़ारों से जोड़े और उन्हें बिना गारंटी के आसान ब्याज पर मशीनरी के लिए लोन दे।

- **'समान ऋण योजना' (बैंकिंग सुधार):** रिज़र्व बैंक (RBI) के माध्यम से एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए, जिससे बैंकों की जवाबदेही तय हो कि 'प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग' (PSL) के तहत अल्पसंख्यकों का लोन कोटा हर हाल में पूरा हो और मुस्लिम युवाओं को अपना स्टार्ट-अप या बिज़नेस शुरू करने में आसानी हो।

निष्कर्ष: आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक सच्चा लीडर वह होता है जो समाज के सबसे कमज़ोर और हाशिए पर खड़े व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलाए। हमें पूरा यकीन है कि 'सबका विश्वास' जीतने की आपकी जो नीयत है, वह इन कदमों से और भी मज़बूत होगी। एक नई कमेटी का गठन और नई शिक्षा व रोज़गार योजनाएं न केवल मुस्लिम समाज के लिए 'नया सवेरा' लाएंगी, बल्कि यह आपके नेतृत्व में 'न्यू इंडिया' (New India) को एक सच्ची वैश्विक महाशक्ति (Global Superpower) बनाने में मील का पत्थर साबित होंगी।

हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने के लिए इस खुले खत पर गंभीरता से विचार करेंगे।

धन्यवाद और जय हिंद!

एक ज़िम्मेदार और विकास चाहने वाला भारतीय नागरिक

लेखक / विचारक : डॉ सैयद नासिर शाह